NIOS PYQ's SOLUTIONS

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS & ANSWERS

APRIL-2025

Your Path to Success

खंड - अ

प्रश्न 1 - निम्नलिखित में से किनके पास दत्तक ग्रहण के लिए पुत्र या 'पलक' को नामित करने की सुविख्यात परम्परा विद्यमान है?

(A) जैन

(B) मुस्लिम

(C) पारसी

(D) बौद्ध

उत्तर - (A) जैन

प्रश्न 2 – वैध हिन्दू विवाह के लिए दूल्हे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

(A) 18 वर्ष

(B) 21 वर्ष

(C) 24 वर्ष

(D) 25 वर्ष

उत्तर - (B) 21 वर्ष

प्रश्न 3 - भारत में यहूदी समुदाय किस धर्म का पालन करते हैं?

(A) यहूदी धर्म

(B) ईसाई

(C) इस्लाम

(D) जैन

उत्तर - (A) यहूदी धर्म

प्रश्न 4 - निम्नलिखित में से कौन-सा हिन्दू कानूनों का स्रोत नहीं है?

(A) वेद

(B) न्यायिक निर्णय

(C) विधायी कानून

(D) महाभारत

उत्तर - (D) महाभारत

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 5 - बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है

(A) सूचनाएँ पाना

(B) दण्ड देना

(C) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उपस्थिति पाना

(D) निचली अदालत को आदेश जारी करना

उत्तर - (C) हिरासत में लिए गए व्यक्ति की उपस्थिति पाना

प्रश्न 6 - निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय उपचारात्मक नहीं है?

(A) क्षतिपूर्ति

(B) विशेष राहत

(C) दण्ड

(D) गलती करने से रोकना

उत्तर - (C) दण्ड

प्रश्न 7 - निम्नलिखित में से कौन-सा दण्ड का सिद्धान्त नहीं है?

(A) सुधारात्मक सिद्धान्त

(B) क्षतिपूर्ति सिद्धान्त

(C) प्रतिकारी सिद्धान्त

(D) आरोपी को क्षमा प्रदान करना

उत्तर - (D) आरोपी को क्षमा प्रदान करना

प्रश्न 8 - सूचना का अधिकार

(A) मौलिक अधिकार है

(B) सांविधानिक अधिकार है

(C) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्मित एक प्रावधान है

(D) मानवाधिकार है

उत्तर - (A) मौलिक अधिकार है

प्रश्न 9 - अधिष्ठायी कानून निम्नलिखित में से किस एक पर कार्य करता है?

(A) सरकार की कार्यशैली

(B) लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(C) देश की राजनीति **(D) संसद की कार्य-प्रणाली**

उत्तर - (B) लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों

प्रश्न 10 - आपराधिक कानून निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गतिविधियों को नहीं दर्शाता ?

(A) राज्य **(B) जनता**

(C) समुदाय **(D) प्रदूषण**

उत्तर - (D) प्रदूषण

प्रश्न 11 - निजी कानून में शामिल है

(A) अनुबंध का कानून **(B) क्षति के नियम**

(C) शासन की शक्तियों के प्रयोग पर सीमाएँ **(D) सम्पत्ति का कानून**

उत्तर - (A)अनुबंध का कानून

प्रश्न 12 - संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कौन लागू करता है?

(A) विधायिका **(B) सर्वोच्च न्यायालय**

(C) कार्यपालिका **(D) उच्च न्यायालय**

उत्तर - (C) कार्यपालिका

प्रश्न 13 - उस प्रक्रिया का नाम चुनिए जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से एक समाधान पर पहुँचा जा सके।

(A) विवाचन **(B) मध्यस्थता**

(C) समझौता **(D) वार्ता**

उत्तर - (B) मध्यस्थता

प्रश्न 14 - कौन-से अधिनियम के अन्तर्गत लोक अदालतों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है?

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(A) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(B) विधिक प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(C) विधिक सेवाएँ अधिनियम, 1987

(D) अनिवार्य सेवाएँ अधिनियम, 1987

उत्तर - (A) विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987

प्रश्न 15 - निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था?

(A) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर

(B) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

(C) जवाहरलाल नेहरू

(D) महात्मा गाँधी

उत्तर - (A) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर

प्रश्न 16 - निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दर्ज नहीं है?

(A) न्याय

(B) समानता

(C) स्वतंत्रता

(D) विविधता

उत्तर - (D) विविधता

प्रश्न 17 - स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत कितनी स्वतंत्रताएँ प्रत्याभूत है?

(A) पाँच

(B) छः

(C) सात

(D) आठ

उत्तर - (B) छः

प्रश्न 18 - कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है?

(A) अनुच्छेद 30

(B) अनुच्छेद 31

(C) अनुच्छेद 32

(D) अनुच्छेद 33

उत्तर - (C) अनुच्छेद 32

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 19 - राष्ट्रपति, राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित करते हैं?

(A) 6 **(B) 8**

(C) 10 **(D) 12**

उत्तर - (D) 12

प्रश्न 20 - निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है?

(A) प्रधानमंत्री **(B) भारत का राष्ट्रपति**

(C) संसद **(D) लोकसभा अध्यक्ष**

उत्तर - (B) भारत का राष्ट्रपति

प्रश्न 21 - निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए:

कॉलम-A	**कॉलम-B**
(a) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869	**(i) पारसी परम्परा**
(b) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	**(ii) यहूदी परम्परा**
(c) अवेस्ता	**(iii) यहूदी निजी कानून**
(d) कासेफ किदुशिम	**(iv) ईसाई कानून**

उत्तर –

(a) भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 — (iv) ईसाई कानून

(b) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 — (iii) यहूदी निजी कानून

(c) अवेस्ता — (i) पारसी परम्परा

(d) कासेफ किदुशिम — (ii) यहूदी परम्परा

प्रश्न 22 - रिक्त स्थानों को भरिए :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

मुस्लिम कानून _____ के _____ को नहीं मानता।

उत्तर – प्रतिनिधित्व, सिद्धान्त

प्रश्न 23 - रिक्त स्थानों को भरिए :

जनहित _____ भारतीय संविधान के अनुच्छेद _____ में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप है।

उत्तर – याचिका, अनुच्छेद 39A।

प्रश्न 24 - सही या गलत लिखिए :

(क) आपराधिक कानून में नशा बचावों में से एक बचाव है।

(ख) आपराधिक कानून में दिमागी खराबी को बचाव के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

उत्तर –

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 25 - सही या गलत लिखिए :

(क) आपराधिक कानून राज्य के कानूनों के उल्लंघन पर कार्य करते हैं।

(ख) अधिष्ठायी कानून अपराध एवं उसके उपचारों को परिभाषित करता है।

उत्तर -

(क) सही

(ख) सही

प्रश्न 26 - सही या गलत लिखिए :

(क) लोक कानून उन मुद्दों पर कार्य करते हैं जो व्यक्तियों, नागरिकों अथवा राज्य से संबंधित नहीं होते।

(ख) लोक कानून सरकारी अधिकारियों के कार्यों एवं शक्तियों से सम्बद्ध होते हैं।

उत्तर -

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(क) गलत

(ख) सही

प्रश्न 27 - रिक्त स्थानों को भरिए :

प्रक्रियात्मक कानून अधिकारों के _____ करने की विधि और इनके उल्लंघन की स्थिति में _____ प्राप्त करने के तरीके निर्धारित करते हैं।

उत्तर – प्रवर्तन, उपाय।

प्रश्न 28 - सही या गलत लिखिए :

(क) लोक अदालतें कम कीमत पर तीव्र न्याय प्रदान करती हैं।

(ख) लोक अदालतों का संचालन ग्राम पंचायतें करती हैं।

उत्तर -

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 29 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वार्ता (बातचीत) _____ हल करने हेतु _____ का एक अन्य रूप है।

उत्तर - विवाद, वैकल्पिक विवाद समाधान।

प्रश्न 30 - निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(क) कौन-से संशोधन ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया था?

(ख) प्रारम्भ में भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार दर्ज थे?

उत्तर –

(क) 24वां संशोधन अधिनियम, 1971

(ख) सात (संपत्ति का अधिकार हटने से पहले)

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 31 - सही या गलत लिखिए :

(क) मौलिक अधिकार न्यायसंगत नहीं हैं।

(ख) सम्पत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।

उत्तर –

(क) गलत

(ख) सही

प्रश्न 32 - रिक्त स्थानों को भरिए :

उच्च न्यायालय का _____ नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास किसी न्यायिक पद पर काम करने का _____ वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

उत्तर – न्यायाधीश, दस।

प्रश्न 33 - रिक्त स्थानों को भरिए :

किसी राज्य की _____ के _____ सदन को विधान परिषद् कहते हैं।

उत्तर – विधानमंडल, उच्च।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 34 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वर्ष _____ में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन _____ में किया गया था।

उत्तर – 1992, रियो डी जनेरियो।

प्रश्न 35 - रिक्त स्थानों को भरिए :

_____ हाउस गैसों के उत्सर्जन का कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक _____ स्तर पर किया गया उपाय है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर - ग्रीन, अंतर्राष्ट्रीय ।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 34 - सही या गलत लिखिए :

(क) उपभोक्ता विवाद निवारण एजेन्सियों को तीन भिन्न स्तरों पर स्थापित किया गया है।

(ख) भारत में उपभोक्ता आंदोलन का लक्ष्य व्यापारियों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करना है।

उत्तर –

(क) सही

(ख) गलत

प्रश्न 35 - रिक्त स्थानों को भरिए :

वर्ष 2002 में _____ अधिनियम को _____ में प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए लागू किया गया था।

उत्तर – प्रतिस्पर्धा, बाजार ।

खंड - ब

प्रश्न 36 - 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून' के बीच कोई दो अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - 'अधिष्ठायी कानून' और 'प्रक्रियात्मक कानून' के बीच दो मुख्य अंतर :

अंतर का आधार	अधिष्ठायी कानून (Substantive Law)	प्रक्रियात्मक कानून (Procedural Law)
1. कार्य	यह अधिकारों, कर्तव्यों और अपराधों को परिभाषित करता है	यह उन कानूनों को लागू करने का तरीका (प्रक्रिया) बताता है।
2. उद्देश्य	यह बताता है कि "कानून क्या है"।	यह बताता है कि "न्याय कैसे मिलेगा"।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 37 - किसी संवैधानिक सरकार के किन्हीं दो लक्षणों की परख कीजिए।

उत्तर - संवैधानिक सरकार के दो लक्षण :

1. **उदार लोकतांत्रिक राज्य :** सरकार का अधिकार कानूनों से सीमित होता है और जनता के चुने प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है।
2. **कल्याणकारी राज्य :** सरकार का उद्देश्य जनता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करना है।

OR / अथवा

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के किन्हीं दो अवयवों को उजागर कीजिए।

उत्तर - भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दो अवयव :

1. **राज्य का स्वरूप :** भारत एक 'संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' है, जहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और देश अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है।
2. **संविधान के उद्देश्य :** नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है।

प्रश्न 38 - समानता के अधिकार के अन्तर्गत प्रदान की गई किन्हीं चार समानताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) के तहत चार प्रमुख समानताएं :

1. **कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) :** सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून से समान सुरक्षा पाएंगे।
2. **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15) :** धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
3. **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) :** सरकारी नौकरी और नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे।
4. **अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17) :** छुआछूत या किसी भी रूप की अस्पृश्यता निषिद्ध और दंडनीय है।

OR / अथवा

स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत दी गई किन्हीं चार स्वतंत्रताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को दी गई चार प्रमुख स्वतंत्रताएं :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** हर नागरिक अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है।
2. **शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता :** नागरिक बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने के अधिकार के अधिकारी हैं।
3. **संघ बनाने की स्वतंत्रता :** नागरिक अपनी इच्छा अनुसार संघ या संगठन बनाने का अधिकार रखते हैं।
4. **भ्रमण की स्वतंत्रता** : नागरिक भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं।

प्रश्न 39 - लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई दो अन्तर उजागर कीजिए।

उत्तर - लोकसभा और राज्यसभा के बीच दो मुख्य अंतर :-

1. **चुनाव प्रक्रिया :** लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

2. **कार्यकाल और स्थायित्व :** लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है और इसके सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं।

प्रश्न 40 - संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्त्व की परख कीजिए।

उत्तर – संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का '**हृदय और आत्मा**' कहा, क्योंकि यह न्यायिक संरक्षण के माध्यम से मौलिक अधिकारों को सुरक्षित और प्रभावी बनाता है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 41 - 'प्रदूषण' शब्द की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – प्रदूषण वह अवांछित परिवर्तन है जो वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों को प्रभावित करता है और मनुष्य तथा पूरे पर्यावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुँचाता है। यह हानिकारक पदार्थों या ऊर्जा के वातावरण में प्रवेश से होता है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 41 - अनुचित कारोबारी व्यवहार में क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले किन्हीं दो अधिनियमों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – अनुचित कारोबारी व्यवहार में क्षतिपूर्ति प्रदान करने वाले दो अधिनियम :

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :** उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करता है और विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों व प्राधिकरणों की स्थापना करता है।
2. **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 :** उपभोक्ता कल्याण की रक्षा करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है और बाजार में किसी संस्था द्वारा अपने प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकता है।

प्रश्न 42 - 'निजी कानून' का महत्त्व स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – 'निजी कानून' कानून की वह शाखा है जो किसी व्यक्ति और उसके परिवार से संबंधित मामलों से निपटती है । इसका महत्त्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है :-

1. **पारिवारिक मामलों का नियमन :** यह उन सिद्धांतों को निर्धारित करता है जो किसी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण, संरक्षकता और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं ।
2. **अधिकारों और वैधता का निर्धारण :** निजी कानून विवाह की वैधता, पति और पत्नी के संपत्ति के अधिकारों, तलाक, बच्चों की वैधता और वसीयत व उत्तराधिकार के नियमों को तय करता है।
3. **धार्मिक आधार पर अनुप्रयोग** : भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ विभिन्न धर्म हैं, निजी कानून का महत्त्व इसलिए भी है क्योंकि यह अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी के आधार पर लोगों पर लागू होता है और उनकी विशिष्ट परंपराओं का सम्मान करता है ।
4. **सामाजिक व्यवस्था** : यह विवाह के माध्यम से संतान उत्पत्ति और उनके वैधीकरण को मान्यता देता है। साथ ही, जब वैवाहिक जीवन सुचारू नहीं होता, तो यह तलाक या विवाह विच्छेद के लिए आवश्यक तंत्र प्रदान करता है, जिससे दैनिक जीवन के मामलों का समाधान होता है ।

OR / अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

हिन्दू कानून के स्रोतों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - हिन्दू कानून के स्रोतों का अध्ययन इसके विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

A. प्राचीन स्रोत:

1. **वेद या श्रुति** : इन्हें हिंदू धर्म के प्राथमिक ग्रंथ और ईश्वरीय कानून माना जाता है, जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए थे ।
2. **स्मृतियाँ :** ये वेदों में निहित नियमों की पूरक व्याख्या प्रदान करती हैं, हालांकि ये हमेशा स्पष्ट नहीं थीं और सभी स्थितियों को कवर नहीं करती थीं ।
3. **भाष्य और निबंध** : कानूनों के विश्लेषण, व्यवस्थापन और एकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनका विकास हुआ।
4. **रिवाज** : यह कानून का एक महत्वपूर्ण प्राचीन स्रोत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

B. आधुनिक स्रोत :

1. **साम्या, न्याय और अच्छा अंतःकरण :** किसी विशिष्ट कानून के अभाव में या संघर्ष की स्थिति में, निष्पक्षता और न्याय के इन सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसका मूल ब्रिटिश प्रशासन में है ।
2. **न्यायिक निर्णय :** न्यायालयों के फैसले हिंदू कानून का सबसे उपजाऊ और व्यावहारिक स्रोत माने जाते हैं।
3. **विधायिका** : यह एक अतिरिक्त स्रोत है जिसमें संसद द्वारा पारित अधिनियम शामिल हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)। ये अधिनियम हिंदू कानून के प्राचीन नियमों को घोषित, रद्द या संशोधित करते हैं ।

प्रश्न 43 - आपराधिक कानून में किन्हीं चार बचावों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – आपराधिक कानून में बचाव मुख्य रूप से 'दोषी मस्तिष्क' की अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं। आपराधिक कानून में किन्हीं चार बचावों की व्याख्या :-

1. **दोषी इरादे का अभाव :** आपराधिक कानून का एक मूलभूत नियम है कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं माना जाता जब तक कि उसे 'दोषी इरादे' के साथ न किया गया हो। इस सिद्धांत को लैटिन कहावत ***"actus non facit reum, nisi mens sit rea"*** द्वारा समझाया गया है । यदि किसी कार्य में दोषी मन शामिल नहीं है, तो वह अपराध नहीं बनता ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **अस्वस्थ मस्तिष्क :** यदि कोई व्यक्ति 'अस्वस्थ मस्तिष्क' का है, तो कानून यह मानता है कि उसने वह गलत कार्य बिना किसी दोषी इरादे के किया है। चूँकि उसे अपने कार्य की प्रकृति या उसके गलत होने का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
3. **नशा :** जिस प्रकार अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को छूट मिलती है, उसी प्रकार एक 'नशे में धुत व्यक्ति' को भी बचाव प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि नशे की हालत में व्यक्ति ने वह कार्य बिना किसी दोषी इरादे के किया है, अतः उसे दंडित नहीं किया जा सकता।
4. **अनजाने में किया गया कार्य :** यदि कोई व्यक्ति किसी को मारता है, तो वह केवल तभी उत्तरदायी होगा यदि वह प्रहार जानबूझकर किया गया हो । इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य अनजाने में या दुर्घटनावश होता है जहाँ इरादा मौजूद नहीं है, तो वह बचाव का आधार बन सकता है।

OR / अथवा

आपराधिक कानून के दो सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - आपराधिक कानून के दो सिद्धान्तों की व्याख्या :

1. **'मेन्स रिया' या दोषी मस्तिष्क का सिद्धांत :** यह आपराधिक कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार, केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उस कार्य के पीछे 'दोषी मन' न हो। अपराध गठित करने के लिए मानसिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल अपहरण करने के बारे में सोचता है लेकिन कोई कार्य नहीं करता, तो वह अपराधी नहीं है; इरादे के साथ कार्य का होना आवश्यक है।

2. **संयुक्त दायित्व का सिद्धांत :** सामान्यतः एक व्यक्ति केवल अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार होता है । लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक व्यक्ति को दूसरों के कार्यों के लिए भी संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38 और 149 आदि इससे संबंधित हैं।

   उदाहरण के लिए, यदि 'सामान्य उद्देश्य' वाली एक गैरकानूनी सभा का कोई सदस्य कोई अपराध करता है, तो उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस कार्य के लिए समान रूप से जिम्मेदार माना जाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 44 - ऐसे किन्हीं चार क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए जिनसे प्रक्रियात्मक कानून का संबंध है।

उत्तर - प्रक्रियात्मक कानून के अंतर्गत आने वाले चार प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

1. **अधिकार क्षेत्र :** प्रक्रियात्मक कानून न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। इसमें संघर्ष के संदर्भ में और घरेलू संदर्भ में दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार शामिल हैं। यह निर्धारित करता है कि किस न्यायालय के पास किस मामले की सुनवाई का अधिकार है।
2. **कानूनी कार्यवाही और सुनवाई :** यह कानून पूरी कानूनी कार्यवाही को नियंत्रित करता है। इसमें समन , अभिवचन, और मुकदमे की सुनवाई शामिल है। यह वह तंत्र है जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया से संबंधित है ।
3. **साक्ष्य और जांच तंत्र :** प्रक्रियात्मक कानून पुलिस और न्यायाधीशों द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने के तंत्र प्रदान करता है। इसमें तलाशी, गिरफ्तारी, जमानत और मुकदमे के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शामिल है।
4. **निर्णय और निष्पादन :** मुकदमे के अंत में निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया और उसके बाद उस निर्णय का निष्पादन भी इसी कानून के अंतर्गत आता है । यह अधिकारों को लागू करने या उनके उल्लंघन के लिए निवारण प्राप्त करने की विधि निर्धारित करता है।

प्रश्न 45 - सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को विश्लेषित कीजिए।

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है वे मामले जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, बिना किसी निचली अदालत में जाए। इसे मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. **विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार :** अनुच्छेद 131 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय को संघीय ढांचे से जुड़े विवादों को सुलझाने का एकमात्र अधिकार है। इसमें निम्नलिखित विवाद शामिल हैं:

a) भारत सरकार (संघ) और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद।

b) एक तरफ भारत सरकार और कोई राज्य, और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्य।

c) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद। भारत में किसी अन्य न्यायालय को ऐसे विवादों की सुनवाई करने की शक्ति नहीं है।

2. **रिट क्षेत्राधिकार :** सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। इसके तहत न्यायालय को निम्नलिखित रिट जारी करने की शक्ति है:

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

a) **बंदी प्रत्यक्षीकरण :** किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत/नजरबंदी से मुक्त कराने के लिए।

b) **परमादेश :** किसी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देने के लिए।

c) **प्रतिषेध :** किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए।

d) **अधिकार पृच्छा :** किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधानिकता की जाँच करने के लिए।

e) **उत्प्रेषण :** किसी मामले को निचली अदालत या न्यायाधिकरण से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उसके निर्णय को रद्द करने के लिए।

इन रिटों के अलावा, न्यायालय कार्यपालिका को उचित निर्देश और आदेश भी जारी कर सकता है।

OR / अथवा

'न्यायिक सक्रियता' पद का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - 'न्यायिक सक्रियता' भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक नई प्रवृत्ति है, जो मुख्य रूप से जनहित याचिका (PIL) के उदय के साथ सामने आई है। इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है :-

1. **उत्पत्ति और अर्थ :** स्वतंत्रता के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने बदलते समाज की जरूरतों के अनुसार कानूनों को नया रूप देने का प्रयास किया है। जनहित याचिका (PIL), जिसे प्रो. उपेंद्र बख्शी ने "सामाजिक कार्रवाई याचिका" (Social action litigation) कहा है, ने न्यायिक सक्रियता के लिए नए रास्ते खोले हैं।
2. **उद्देश्य :** इसका मुख्य उद्देश्य आम आदमी और गरीबों तक न्याय पहुँचाना है। यह उन लोगों को राहत प्रदान करता है जो पारंपरिक मुकदमेबाजी के कठोर और महंगे सिस्टम का सामना नहीं कर सकते।
3. **कार्यपालिका पर नियंत्रण :** न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका सरकारी मनमानी, लापरवाही और कार्यपालिका के उदासीन रवैये पर प्रभावी रोक लगाती है और उन्हें उनकी गलतियों के लिए जवाबदेह बनाती है।
4. **महत्वपूर्ण उदाहरण :** *केशवानंद भारती केस* (मौलिक अधिकार), *नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य* (हिरासत में मृत्यु पर मुआवजा और 'संप्रभु प्रतिरक्षा' के दावे को खारिज करना) जैसे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय की रचनात्मक भूमिका और न्यायिक सक्रियता के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह न्यायपालिका को सामाजिक न्याय का एक साधन बनाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 46 - राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के संगठन का वर्णन कीजिए।

उत्तर - राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 4 के अनुसार, NGT एक विशिष्ट न्यायिक निकाय है जिसमें कानूनी और पर्यावरण विशेषज्ञों का संतुलन होता है। इसकी संरचना निम्नलिखित है :

1. **अध्यक्ष :** अधिकरण का प्रमुख एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इस पद के लिए केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही योग्य होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के परामर्श से की जाती है।

2. **न्यायिक सदस्य :** अधिकरण में न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होने चाहिए।ये सदस्य विधिक पृष्ठभूमि से आते हैं और आमतौर पर उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो मामलों के कानूनी पहलुओं को देखते हैं।
3. **विशेषज्ञ सदस्य :** न्यायिक सदस्यों की तरह, विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या भी न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 निर्धारित की गई है। इनके पास पर्यावरण विज्ञान, वन संरक्षण, या संबंधित विषयों में विशेष तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव (जैसे कि 15 वर्षों का प्रशासनिक या वैज्ञानिक अनुभव) होना अनिवार्य है।
4. **संरचना का उद्देश्य :** न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों का यह मिश्रण इसलिए बनाया गया है ताकि अधिकरण न केवल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करे, बल्कि जटिल वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मुद्दों (जैसे प्रदूषण का स्तर, पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव) को भी सही ढंग से समझकर निर्णय ले सके।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 46 - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दो कार्य निम्नलिखित हैं :-

1. **उपभोक्ताओं का हित और कल्याण :** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए कार्य करें। यह अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकता है ताकि उपभोक्ताओं को सही कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं मिल सकें। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ रहे, जिससे अंततः उपभोक्ताओं को फायदा हो।

2. **स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना :** आयोग का दूसरा प्रमुख कार्य देश की आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के तेज और समावेशी विकास

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(inclusive growth) को बढ़ावा देना है। आयोग प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों (anti-competitive agreements) और बाजार में किसी संस्था द्वारा अपनी प्रमुख स्थिति (dominant position) के दुरुपयोग को रोकता है, ताकि सभी व्यवसायों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले।

प्रश्न 47 - भारतीय संविधान में दिए गए 'स्वतंत्रता के अधिकार' के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 19-22) में निहित 'स्वतंत्रता का अधिकार' नागरिक स्वतंत्रता का मूल है। यह अधिकार व्यक्ति को कार्यपालिका के दमनकारी कृत्यों से बचाता है और लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अनिवार्य है। इसका महत्त्व निम्नलिखित बिंदुओं में विश्लेषण किया जा सकता है :-

1. **व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं (अनुच्छेद 19) :** यह नागरिकों को भाषण, सभा, संघ, भ्रमण, निवास और पेशे की छह स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये व्यक्तित्व विकास और लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।
2. **दोषसिद्धि से संरक्षण (अनुच्छेद 20) :** यह मनमाने दंड से बचाता है। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती और न ही उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
3. **जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा (अनुच्छेद 21) :** यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यह गारंटी देता है कि कानून की प्रक्रिया के बिना किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। इसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षा का अधिकार (21A) भी शामिल है।
4. **गिरफ्तारी से संरक्षण (अनुच्छेद 22) :** यह पुलिस की मनमानी को रोकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है।
5. **उचित प्रतिबंध :** ये अधिकार असीमित नहीं हैं। देश की सुरक्षा और संप्रभुता के हित में राज्य इन पर 'उचित प्रतिबंध' लगा सकता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन बनाए रखता है।

OR / अथवा

आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़े किन्हीं चार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को उजागर कीजिए।

उत्तर - संविधान के भाग-IV में वर्णित DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत को एक 'कल्याणकारी राज्य' बनाना है। इससे जुड़े चार प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. **लोक कल्याण और सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 38) :** राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। यह आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **संसाधनों का उचित वितरण (अनुच्छेद 39) :** राज्य अपनी नीतियां इस प्रकार बनाएगा कि सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन मिलें और भौतिक संसाधनों का वितरण 'सामूहिक हित' में हो। यह धन के संकेंद्रण को रोकेगा और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' सुनिश्चित करेगा ।

3. **काम की न्यायसंगत दशाएं (अनुच्छेद 42) :** राज्य काम के लिए मानवोचित और न्यायसंगत परिस्थितियां तैयार करेगा। इसमें महिलाओं के लिए 'प्रसूति सहायता' (Maternity Relief) का प्रावधान भी शामिल है ।

4. **निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग (अनुच्छेद 43) :** सभी कामगारों को एक शिष्ट जीवन स्तर और 'निर्वाह मजदूरी' सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 'कुटीर उद्योगों' को बढ़ावा देना भी राज्य का कर्तव्य है ।

प्रश्न 48 - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की विभिन्न तकनीकों के महत्त्व को परखिए।

उत्तर - वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के अंतर्गत विवादों को सुलझाने की कई तकनीकें शामिल हैं, जिनका अपना-अपना महत्त्व है :-

1. **मध्यस्थता :** यह पारंपरिक मुकदमेबाजी की तुलना में कम खर्चीला और तेज है । इसमें एक या अधिक निष्पक्ष 'मध्यस्थ' (Arbitrators) होते हैं, जो विवाद सुनते हैं और एक निर्णय ('पंचाट' या Award) देते हैं जो दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है । यह वाणिज्यिक और तकनीकी विवादों के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि मध्यस्थ उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है ।
2. **सुलह :** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तीसरा पक्ष ('सुलहकर्ता') विवाद को सुलझाने में मदद करता है । सुलहकर्ता विवाद के गुणों पर अपनी राय दे सकता है और एक समझौता निपटान का प्रस्ताव रख सकता है । यह प्रक्रिया पूरी तरह से स्वैच्छिक और गोपनीय होती है ।
3. **मध्यस्थता/मीडिएशन :** इसमें एक तटस्थ 'मध्यस्थ' (Mediator) पक्षों को बातचीत करने और समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है । वह सुलहकर्ता की तरह अपनी राय नहीं थोपता, बल्कि केवल संचार और समझौते को सुगम बनाता है । यह पारिवारिक और व्यक्तिगत विवादों के लिए बहुत प्रभावी है क्योंकि इसमें संबंधों को बिगड़ने से बचाया जा सकता है।
4. **लोक अदालत :** यह भारत में ADR का एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों में लंबित छोटे और सामान्य मामलों के भारी बोझ को कम करना है । यह कम खर्चीला है और त्वरित न्याय प्रदान करता है । लोक अदालत का निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री के समान माना जाता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5. **वार्ता :** यह सबसे आम तरीका है जहाँ पक्ष आपस में बात करके और सौदेबाजी करके समाधान निकालते हैं।

OR / अथवा

प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर - 'प्ली बार्गेनिंग' आपराधिक मामलों में विवाद समाधान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 265 A के तहत पेश किया गया है । इसका विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है :-

1. **अवधारणा :** प्ली बार्गेनिंग का अर्थ है कि यदि कोई आरोपी अपने ऊपर लगाए गए आरोप (offence alleged) को स्वीकार करने के लिए तैयार है (plead guilty), और पीड़ित के साथ मामले को सुलझाने (compromise) की इच्छा व्यक्त करता है, तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है ।
2. **शर्तें :** यह प्रक्रिया केवल न्यायालय की सहमति (consent of the Court) से ही संभव है। इसका उपयोग उन मामलों में नहीं किया जा सकता जो गंभीर अपराधों (heinous crimes) की श्रेणी में आते हैं।
3. **उद्देश्य** : इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य अदालतों के कार्यभार (work load) को कम करना और मामलों का त्वरित निपटान (speedy disposal) सुनिश्चित करना है ।
4. **लाभ** : इससे आरोपी को कम सजा मिल सकती है और पीड़ित को जल्दी न्याय मिल जाता है। यह अदालती प्रक्रिया के समय और खर्च को बचाता है। यह उन आपराधिक मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है जो मामूली प्रकृति (trivial in nature) के होते हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 49 - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया के किन्हीं चार प्रमुख बिन्दुओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के विनियमन की प्रक्रिया के चार प्रमुख बिंदु :-

1. **प्राधिकार प्राप्त करना :** यह प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। कोई भी व्यक्ति या उद्योग जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करता है, उसका संग्रह, परिवहन, भंडारण या निपटान करता है, उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) से 'प्राधिकार' प्राप्त करना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करता है कि उद्योग के पास कचरे को संभालने की तकनीकी क्षमता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **पैकेजिंग और लेबलिंग :** खतरनाक कचरे को संभालने के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि है। कचरे को ऐसे कंटेनरों में पैक किया जाना चाहिए जो रिसाव-रोधी हों। कंटेनरों पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाना आवश्यक है, जिस पर कचरे की प्रकृति, खतरे का प्रकार और आपातकालीन स्थिति के लिए निर्देश लिखे होने चाहिए ताकि परिवहन और भंडारण के दौरान किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके।
3. **सुरक्षित परिवहन :** खतरनाक अपशिष्ट का परिवहन केवल उन्हीं वाहनों से किया जाना चाहिए जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों। इसके अलावा, नियमों में कचरे की **'सीमा पार आवाजाही'** पर भी कड़े प्रावधान हैं ताकि एक राज्य या देश का कचरा अवैध रूप से दूसरे स्थान पर डंप न किया जा सके।
4. **उपचार और निपटान :** खतरनाक कचरे का निपटान खुले पर्यावरण में करना सख्त मना है। इसे केवल सरकार द्वारा अधिकृत 'सुरक्षित लैंडफिल साइटों' (Secure Landfills) या 'इंसिनरेटर' (भस्मीकरण संयंत्र) में ही नष्ट किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य मिट्टी और भूजल को जहरीला होने से बचाना है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 49 - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के किन्हीं चार तरीकों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर - उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के चार प्रमुख तरीके:

1. **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 :** इसे उपभोक्ताओं का 'मैग्ना कार्टा' माना जाता है। यह अधिनियम दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है । यह उपभोक्ताओं को आसानी से और कम खर्च में न्याय पाने का कानूनी ढांचा देता है ।
2. **त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र :** उपभोक्ताओं को त्वरित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए अधिनियम के तहत तीन स्तरों पर अर्ध-न्यायिक व्यवस्था की गई है: (a) जिला फोरम, (b) राज्य आयोग, और (c) राष्ट्रीय आयोग । असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता ऊपरी स्तर पर अपील भी कर सकता है ।
3. **उपभोक्ता जागरूकता :** उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए उन्हें उनके 6 अधिकारों (सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा) के प्रति जागरूक करना आवश्यक है । सरकार "जागो ग्राहक जागो" अभियान के माध्यम से यह कार्य करती है ।
4. **केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद :** यह परिषद उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाती है । यह सुनिश्चित करती है कि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता और कीमत पर वस्तुएं प्राप्त हों ।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Thank you!

We hope you found this material helpful. We wish you the very best for your examination.

Strive for Excellence – Your Path to Success